भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2659

19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

2659. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो महीनों के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने ऐसी प्रवृत्ति को बदलने के लिए क्या नीतिगत और कार्यक्रमगत कार्रवाई की है; और

(घ) क्या बिक्री में इस प्रकार की गिरावट से भारत के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): जी नहीं। पिछले दो महीनों के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कोई मंदी नहीं देखी गई है। इसके अतिरिक्त, ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों का माह-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

(ख): प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

(ग): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम-इंडिया):** सरकार ने फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II को शुरू में 1 अप्रैल, 2019 से आरंभ पाँच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से अधिसूचित किया।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने दिनांक 15 सितंबर 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम अनुमोदित की। इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

iii. **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम**: सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में देश में 50 गीगावाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, 5 गीगावाट की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

vi. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(घ): इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

*****

अनुलग्नक

तालिका में उल्लिखित विनिर्दिष्ट महीनों के दौरान पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या

तालिका में उल्लिखित विनिर्दिष्ट महीनों के दौरान पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या								
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या	माह							सकल योग
	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर *(अद्यतन स्थिति (15-12-2023) वर्ष 2023 में)	
वर्ष 2022	75,877	80,881	89,014	94,912	1,17,498	1,21,601	1,05,006	6,84,789
वर्ष 2023	1,02,541	1,16,484	1,27,061	1,28,374	1,39,873	1,53,022	51,868	8,19,223

नोट: 1- दिए गए विवरण केंद्रीकृत वाहन 4 के अनुसार डिजिटीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।

2- तेलंगाना और लक्षद्वीप के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि वे केन्द्रीकृत वाहन 4 में नहीं हैं।

******